प्रेषक,

अमित सिंह नेगी, सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में.

मुख्य प्रशासक,

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण.

देहरादून।

आवास अनुभाग—2 देहरादून : दिनांक 6 र्वास्तर, 2017 विषय— राज्य प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक-550/उडा-236/2017-18, दिनांक 14.09.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या—290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016 एवं शासनादेश—294, दिनांक 30.12.2016 के उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्मिकों का वेतन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम—2016 में निहित प्रकिया के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3— उक्त अधिसूचना संख्या—290, दिनांक 28.12.2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापित वेतन इस शर्त / प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस संबंध में

होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

4— प्राधिकरण के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्घ वेतनमान व ए०सी०पी० व्यवस्था (यदि पूर्व में लागू हो) को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०ए०), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—11/XXVII(7)30(14)/2016, दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.

01.2017 से लागू होगी।

5— प्राधिकरण के सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुये रिक्त पदों पर भर्ती / चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी, यदि योजनाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गितमान है, ऐसे पद भर्ती / चयन हेतु शासन की अनुमित प्राप्त की जायेगी, जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेश की व्यवस्थानुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाये, भविष्य में प्राधिकरण के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जाये।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०प०सं०—224/xxvii(10)/2017, दिनांक 30.11.2017 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किए जा रहें है।

भवदीय, (अमित सिंह नेगी) सचिव संख्या—(१८२-/ V-2-2017—21(आ०) / 2017—तद्दिनांक । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :— (1) मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून। (2)

(3) वित्त अनुभाग-07, उत्तराखण्ड शासन।

गार्ड बुक।

आज्ञा से, (प्रेम सिंह राणा) अनु सचिव